राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों में सम्बन्ध —

① राजकोषिय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधिन होता है।
मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है।

② राजकोषीय नीति मांग पक्ष को प्रभावित करती है।
मौद्रिक नीति का प्रभाव लागत पर पड़ता है।

③ राजकोषिय नीति के प्रभाव तात्कालिक होते जबकि मौद्रिक नीति के प्रभाव समय अन्तराल से उत्पन्न होता है।

④ मन्दी की स्थिति में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है।

⑤ मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था का केवल संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है जबकि राजकोषीय नीति असंगठित क्षेत्र को भी समान रूप से प्रभावित करती है।

⑥ मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष होता जबकि राजकोषीय नीति क्रयशक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

क्राउडिंग आउट प्रभाव :—

यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं।

* मुद्रा-स्फीति का एक मुख्य कारण व्यय में वृद्धि का होना है। मुद्रा-स्फीति की स्थिति में व्यय में कमी तथा मंदी की स्थिति में वृद्धि करना आवश्यक होता है।

* भारत में सार्वजनिक व्यय राजस्व एवं पूंजी व्यय में किया जाता है।

* स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में राजकोषीय नीति की भूमिका तटस्थ (Neutral) या अहस्तक्षेपक होती है क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विभाजन एवं सभी आर्थिक क्रियाएं मांग-पूर्ति की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है।

* राजकोषीय नीति का प्रारम्भ – 1936 (लार्ड किन्स)

मुद्रा स्फीति (Inflation) —

<u>क्राउथर</u> - वस्तुओं का मुल्य बढ़ रहा हो, मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो।

<u>फ्रीडमैन</u> - उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक

<u>कीन्स</u> - अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार में होने के बाद मूल्य वृद्धि।

<u>कारण</u> :—

1) <u>मांगजन्य</u> :— हीनार्थ प्रबन्धन (घाटे की वित्त व्यवस्था)
सार्वजनिक व्यय में वृद्धि
करारोपण में कमी

2.) पूर्तिजन्य :- { उत्पादन मे कमी
निर्यात मे वृद्धि, आय में कमी
जमाखोरी

3.) लागतजन्य :- मजदुरी, लाभ, परिवहन लागत आदि में वृद्धि।

रोकने के उपाय :-

(1.) राजकोषीय / वित्तिय नीति

(2.) मौद्रिक नीति :- { बैंक दर में वृद्धि
खुले बाजार की क्रिया
VRR (CRR, SLR) में वृद्धि

(3.) अन्य उपाय :- मुल्य नियन्त्रण, राशनिंग, उत्पादन में वृद्धि, मजदुरी, लाभ वृद्धि आदि के नियन्त्रण से

प्रकार :-

1.) रेंगती हुई :- मुल्य स्तर में 1% वार्षिक (10% दशकीय) वृद्धि

2.) चलती हुई - 3-4% वार्षिक (30-40% दशकीय) वृद्धि

3.) भागती / कुदती हुयी - 10% वार्षिक (100% दशकीय) वृद्धि या अधिक

भारत में योजना आयोग 4% स्फीति तथा केन्द्र 5-10% स्फीति आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानते है।